मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि गाजीपुर जनपद की इस खेती और फैक्टरी की तत्काल रक्षा की जाये। यहां किसानों को उन्नतशील बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों को फैक्टरी की ओर से उपलब्ध कराया जाए। प्रति वर्ष 25 प्रतिशत की दर से की जा रही कटौती को रोक कर व्यावसायिक पैमाने पर खेती कराई जाए। प्रति हैक्टेयर अफीम की मांग पुराने स्तर, अर्थात् 12 किलो रखी जाए। फसल बीमा योजना करके उसकी खेती की सुविधा लघु एवं सीमान्त कृषकों को दी जाए। अफीम काश्तकारों के परिवार को फैक्टरी में कार्य दिया जाए।

प्राय: यह सर्वविदित है कि अफीम तोलने, उसके क्षरण एवं नमूने के नाम पर अधिकारी लोग प्राय: गड़बड़ी करते हैं। मूल्य प्राय: किसान को कम दे कर खाते में कुछ और मूल्य दर्ज करते हैं। कई प्रकार के रेट बनाये गए हैं। तुरन्त इन सभी गड़बड़ियों पर नियन्त्रण किया जाए। गाजीपुर अफीम के नशे में सो रही अफसरशाही को चिन्तित किया जाए। मान्यवर, यदि शीघ्र गाजीपुर अफीम की खेती पर ध्यान नहीं दिया गया तो मुल्क को प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा में काफी कमी होगी। वर्तमान अफसरशाही और फैक्टरी की व्यवस्था ने किसानों को हताश कर दिया है। दिन प्रति दिन खेती का विस्तार कम होता जा रहा है। अभी समय है यदि यहां सर्वेक्षण करा कर सरकार रुचि ले तो गाजीपुर अफीम एवं अफीमजन्य अन्य रासायनिक तत्वों के उत्पादन में एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया के मानचित्र पर अपना महत्व-पूर्ण स्थान रखा जा सकता है।

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House will take up further consideration of the Motion of Thanks on President's Address. Shri P. Namgyal to continue his speech He has already taken five minutes. He may take another five minutes. If he will take more time then other colleagues of his party may not get opportunity to speak. So, I request him to conclude in another five minutes.

SHRI P. NAMGYAL (Ladakh): I will take half an hour.

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, कल जब मैं बोल रहा था तो मैं वहां पर फण्डस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बतला रहा था। लद्दाख के दो डिस्ट्रिक्टस लेह और कारगिल में वे फण्डस को आबादी के बेसिज़ पर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किये थे, इसी से मौजूदा झगड़ा शुरू हुआ..

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK: (Annantnag): On a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is the Point of Order?

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK: He is talking about law and order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what rule are you raising the point of order?

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK: 376.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order.

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK: I have a right to raise my point of order

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order.

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK: I should be given opportunity to answer every issue; I will take one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please. There is no Point of Order.

Mr. Nomgyal to continue his speech.

श्री पो० नामग्याल : डिप्टी स्पीकर साहब, आप को पता ही है कि गाडगिल फार्मूले में 60 परसेंट पापुलेशन पर वेटेज दी गई है, लेकिन वह जम्मू-काश्मीर में एप्लीकेबिल नहीं है, क्योंकि जब शेख

[श्री पी०नामग्याल]

साहब पावर में आये तो उन्होंने कहा कि गाडगिल फार्मूले के मुताबिक 60 परसेंट पापुलेशन पर वेटेज है, जब कि जम्मू-काश्मीर में पापुलेशन कम है और एरिया ज्यादा है। उन्होंने नेशनल डेवेलेपमेंट कान्सिल और प्लानिंग कमीशन के सामने इब फार्मूला के खिलाफ आवाज उठायी और अपने मकसद में कामयाब हो गये। अब जम्मू-काश्मीर पर गाडगिल फार्मूला एप्लीकेबिल नहीं है, जो फण्डस उन को मिलते हैं वे ज्यादातर एरिया, वेकवर्डनेस और गुरबत के लिहाज से मिलते हैं, लेकिन इस चीज को उन्होंने लेह और कारगिल में लागू नहीं किया और कहा कि वहां पापुलेशन के मुताबिक मिलेगा क्योंकि लद्दाख में आबादी कम है। इसी बात को लेकर 1979 में झगड़ा शुरू हुआ।

जब ये बातें शुरू हुई तो हम ने कहा कि आप सेन्टर से पापुलेशन के बेसिज पर नहीं, बल्कि एरिया के बेसिज पर पैसा लेते है तो हमारा एरिया तो पूरी स्टेट का 2/3 हिस्सा है, हम को भी उसी हिसाब से पैसा मिलना चाहिये। हमारा यह मकसद नहीं था कि स्टेट के 2/3 एरिया के हिसाब से हम को फण्डस मिले, बल्कि एरिया, पापुलेशन, डिस्टेंस और गुरबत को ख्याल में रख कर फण्ड्स दिया जाना चाहिये। हम बहुत फार-फलंग एरिया में बसते हैं, हमारे एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। लेकिन हमारी बातों को नहीं माना गया और 1980 में यहीं से झगड़े का आगाज हुआ, लद्दाख में इस सवाल को लेकर एजीटेशन हुआ। हम ने 27 प्वाइन्टस को लेकर अपनी मांग पेश की, जिन में तीन-चार मेजर ईशूज थे और कुछ छोटे-मोटे मसले थे। उन में एक प्वाइन्ट यह था कि सारे लद्दाख एरिये को शेडयूल्ड-ट्राइब्ज डिक्लेअर किया जाय। रीजनल-आडोनामी विद-इन-दि स्टेट आफ जम्मू एण्ड काश्मीर कांस्टियूशन खास तौर से फाइनेन्शल मैटर्स में दी जाय, जिस में ला-एण्ड आर्डर शामिल नहीं था। हम ने उस में एडमिनिस्ट्रेशन की बात कभी नहीं कही है। अभी कल ही जम्मू-काश्मीर असेम्बली में गर्वनर के एडेस पर जवाब देते हुए वहां के फाइनैन्स मिनिस्टर श्री डी० डी० ठाकुर हमारे बारे में बहुत डिस्टार्टेड फैक्ट्स पेश किये हैं, जो आज के अखबारों में शाया हुए हैं। में समझता हूं इस तरह की बातों की सारी दुनियां और मुल्क में गलतफहमी पदा करने और गुमराह करने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है—लद्दाख के लोग सैप्रेट कैबिनेट की मांग करते हैं—यह बिल्कुल गलत बात है। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं उन बातों को पढ़ कर सुना सकता हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि शेडयूल्ड ट्राइब्स के बारे में प्राइम मिनिस्टर साहिबा के साथ बातचीत की थी और उन्होंने भी (P. M.) यह कहा है कि यह नहीं होना चाहिये, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने उस को नहीं माना है। मुझे बड़ा अफसोस है कि श्री ठाकुर ने प्राइम मिनिस्टर का नाम ले कर उन को भी इस में ड्रेग करने की कोशिश की है जब कि यह ईशू अभी प्राइम मिनिस्टर के सामने नहीं है, क्योंकि काश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत अगर सेन्टर कोई कानून जम्मू-काश्मीर में एप्लाई करना चाहता है तो उस के लिये एप्ली-केशन आर्डर चाहिये। स्टेट गवर्नमेंट का कसेंट चाहिये। जब स्टेट गवर्नमेंट रिकमेंड करेगी कि सब एण्ड सब कानून जम्मू व काश्मीर में लागू करो तब जाकर प्रेजीडेशियल आर्डरान के तहत जम्मू व काश्मीर में सेंटर का कानुन एप्ली-केबिल होता है। अभी तक कोई सिफारिश प्राइम मिनिस्टर के सामने सामने या होम मिनिस्टर के सामने नहीं आई है और होमे मिनिस्टर साहब ने इस हाऊस में दो-तीन बार डिनाई किया है कि कोई ऐसी रिकमेंडेशन

नहीं है । लिहाजा मैं समझता हूं कि जो स्टेटमेंट दिया है, वह सारे फैक्टस पर बेस नहीं करता है और वह सारा डिस्टोर्टेड है ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि कैबिनेट सब कमेटी और लद्दाख एक्शन कमेटी के दर्मयान जो एग्रीमेंट हुआ है, उसको इम्पलीमेंट करने के लिये हमने कहा था । जब कैबिनेट सब-कमेटी लद्दाख आई थी, तो यह एग्रीमेंट हुआ था, जिसके लिये हम यहां तक तैयार हैं कि प्राइम मिनिस्टर की कयादत में या होम मिनिस्टर की कयादात में एक कमेटी बने, जिस के लिये मैं अपोजीशन लीडर्स से भी गुजरारिश करूंगा कि वे भी उसमें नोमीनेटेड हों और वह कमेटी यह देखे कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें क्या क्या वायदे हुये हैं । वे भी उस एग्रीमेंट को पढ़ें और देखें कि हम लोगों ने क्या क्या डिमांड किया है । आपके सामने सारे फैक्टस आ जायेंगे । मैं इस पर और ज्यादा नहीं कहना चाहता बल्कि यह कहूंगा कि जो लिख कर दिया है, उसको इम्पलीमेंट करना चाहिये फंडस के बारे में क्या-क्या कहा गया है एग्रीमेंट में, मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Which Cabinet Sub-Committee are you referring to?

SHRI P. NAMGYAL: This is the agreement reached between the Jammu & Kashmir Cabinet Sub-Committee and the Ladak Action Committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can take something out of it and talk on those lines. But don't read out those agreements.

SHRI P. NAMGYAL: I want to read out only the relevant portion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You need not read it out. You should not mention here the decision of the Jammu & Kashmir Cabinet Sub-Committee.

SHRI P. NAMGYAL: There is no secrecy about this agreement, Sir.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Have you given a copy of it to the Speaker and taken his permission to read it out?

SHRI P. NAMGYAL: No, Sir. But if you permit I will place it on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can take the idea from it and speak on that basis. You can speak in a general way.

SHRI P. NAMGYAL: I will place it on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No. You can speak something by taking some ideas from them. Now, we are having a general discussion on the President's address.

श्री पी० नामग्याल : जनाब मैं यह चाह रहा था कि हाऊस एनलाइटेड हो जाए कि वाकई में क्या चीज है । रोज रोज गलत स्टेटमेंटस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लद्दाख के बारे में निकलते हैं । हमने जो रीजनल आटोनामी की बात कही है वह डेवलपमेंट मैटर्स तक ही महदूद है । लद्दाख को अलग करने की बात नहीं कही है । हम जम्मू व काश्मीर के कांस्टीट्यूशन के तहत ही बात कर रहे हैं ।

मैं यह पहले भी कह चुका हूं और अब फिर किलयर करना चाहता हूं । इसलिये ये डिस्टोर्टेड फैक्टस जो जम्मू व कांश्मीर सरकार प्रेस में दे रही है और एसेम्बली में भी दिये गये हैं, ये सही नहीं हैं । इसलिये मैं इस हाऊस के सामने यह बात रखना चाह रहा था ।

इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में उन्होने हमारे पास लिख कर दिया हुआ है कि वे स्ट्रोंगली रिकमेंड करेंगे सेन्ट्रल गवर्नमेंट को कि लद्दाख के लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिकलेयर किया जाए । और लद्दाख का जो यह इसू है, इस को सेपरेटली लिया जाएगा ।

तीसरा यह इशू था कि जो इन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन लाया है, जम्मू व कश्मीर गवर्नमेंट ने जो डिलिमिटेशन

श्री पी० नामग्याल

कमीशन मुकर्रर किया है, तो उसमें यह कहा था कि जब भी यह मौका आयेगा, तो लद्दाख की एसेम्बली कांस्टीटुयेंसी बढ़ाने की बात पर गौर किया जायेगा। ये सारी बातें हैं। यह शेड्यूल्ड ट्राइब्स का मेन इशु था जो कि वहां का बहुत इम्पोर्टेंट इशु है और जिस पर इन्होंने एग्रीमेंट किया था और जिसके बारे में इन्होंने डिसाइड भी किया था। हम लोगों का यही कहना था कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसको पूरा करो। जब ये वायदे पूरे नहीं किये गये तो इसी मस्ले को लेकर दिसम्बर, 1981 में एजीटेशन शुरू हुआ और 15 जनवरी, 1982 को हमारे तीन लीडर ने डिमांड को प्रेस करने के लिये इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक की और आगे चल कर उनकी हालत खराब हुई।

उसके बाद इन्हीं डिमांण्डस को प्रैस करने के लिये 24 जनवरी को एक जुलूस उस जगह पर जा रहा था जहां तीन लोकल लीडर भूख हड़ताल पर थे। उस पर पुलिस अनप्रवोक्ड और विदाउट वारनिंग फायरिंग की। जब भी फायरिंग करनी होती है तो पहले वारनिंग दी जाती है, फिर हवाई फायरिंग होती है, उसके बाद क्राऊड में रेंडम फायरिंग टांगों के हिस्से में करना होता है। लेकिन वहां पर पुलिस ने इस तरह से फायरिंग की कि बन्दूकों को दीवार पर टारगेट पर रख कर जैसे कि फायरिंग की जाती है। पुलिस की पहली गोली से पहला आदमी मरा, दूसरी गोली से दूसरा आदमी मरा और तीसरी गोली से तीसरा आदमी जख्मी हुआ। इन्डिस्क्रिमिनेट फायरिंग शुरू हो गया। पचास-साठ गोलियां चलाई गई और बहुत से आदमी जख्मी हुये।

इस सबके लिये वहां तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट से तो हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर स्टेट में जंगल का कानून चलता है तो यह सेंटर की जिम्मेदारी बनती है कि वह वहां के हालात को देखे। आज आसाम में क्या हो रहा है, नागालड में क्या हो रहा है, मिजोरम में क्या हो रहा है। जब लोगों को तकलीफे होती हैं, उनकी ग्रिवांसिज को कोई सुनने वाला नहीं होता तो हालत खराब होती है। मैं कहता हूं कि यही हालत लद्दाख में भी कभी न कभी हो सकती है।

लद्दाख के लोगों ने इस मुल्क के लिये बहुत खून बहाया है। 1947 में जब इस मुल्क पर हमला हुआ, कश्मीर में इंवेडर्स आये थे तो लद्दाख के लोगों ने उनका मुकाबला किया था।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please complete it. You are not coming to national issues. You are still in Jammu and Kashmir only. And you are not speaking about the entire Jammu and Kashmir, but only about Ladhak. Please complete. Your own Party Members will be deprived of their chances.

SHRI P. NAMGYAL: I am going to complete, Sir.

उसके बाद 1962 में जब चीन ने इस मुल्क पर हमला किया तो उस वक्त भी लद्दाख के लोग आगे बढ़ कर लड़े थे। फिर पाकिस्तान ने 1965 में हमला किया उस वक्त भी वहां के लोगों ने इस मुल्क के लिये खून बहाया। 1971 की जंग में भी वे लड़े। यह सारी हालत आपके सामने हैं। यह सब होते हुये भी हमारी वहां कोई सुनने वाला नहीं है।

वहां पर फायरिंग करने के बाद पुलिस ने लूटमार शुरू कर दी। यह लूटमार दिन रात चलती रही। कोई देखने वाला नहीं था। वहां पर रेप हुये, घरों के दरवाजे

और खिड़कियां तोड़ डाली गयी । घरों में बच्चों और औरतों की पिटाई की गयी, सामान को बर्बाद किया गया । लूट मार किया गया

इस वक्त वहां पर हालत यह है कि यह जितने हमारे भी पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो लोग पकड़े गये हैं उनको जमानत पर नहीं छोड़ा जा रहा है । चीफ जुडीशियल मेजिस्ट्रेट एस० पी० और डी० सी० से पूछता है कि जमानत पर छोड़ या न छोड़ूं । इस तरह की वहां के कानून की हालत है । इस वक्त भी वहां पर धरना जारी है । औरतें भी धरने पर बैठी हुई हैं ।

जो लोग जेल में हैं उनको मिनिमम फेसिलिटीज नहीं दी जा रही है । पानी तक नहीं दिया जा रहा है । हालांकि ये लोग ज्यूडिशियल लाक-अप में हैं । सरकार को चाहिये कि उनको मिनिमम फेसिलिटीज दे ।

वहां पर कभी-कभी तो माइनस 20 तक टेंप्रेचर हो जाता है, लेकिन हीटिंग अरेंजमेंट तो दूर उनको कम्बल तक नहीं दिये गये हैं । खाने के लिये उनको कुछ नहीं दे रहे हैं । टाउन से काफी दूर लोगों को रखा है और उनके रिश्तेदारों को वहां पहुंचने के लिये ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता है ।

इन सब हालातों को देखते हुये मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि किसी न किसी मिनिस्टर को जरूर वहां पर फौरन जाने की जरूरत है नहीं तो हालात और अधिक खराब हो सकते हैं । मैं होम-मिनिस्टर साहब का मशकूर हूं कि वे पिछले दिनों गये थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वहां नहीं जा सके । अबस मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वे किसी को वहां पर अवश्य भेंजें । नहीं तो लोगों का आप पर से विश्वास उठ जायगा ।

मैं केवल सरकार से ही नहीं बल्कि पूरे सदन से अपील करता हूं और विरोधी दल से भी अपील करता हूं कि वह भी अपना नुमाइंदा भेजे ।

आप देख लीजिए जो हमारा एग्रीमेंट है । अगर आप कहें कि हम गल्ती पर हैं तो हम मानने के लिए तैयार हैं । अगर हम गलती पर नहीं हैं तो जम्मू-कश्मीर सरकार से कहा जाए कि जो एग्रीमेंट हुआ है इसको इम्प्लीमेंट करे । इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते हैं

इसके साथ ही जो प्रेसीडेंट साहब का एड्रस है उसका म समर्थन करता हूं ।

[شری پی - نام گیال (لداخ) :

جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب - کل جب میں بول رہا تھا تو میں یہاں پر فنڈس کے ڈسٹری بیوشن کے بارے میں بتلا رہا تھا - لداخ کے دو ڈسٹرکٹ - لیہہ اور کارگل میں وہ فنڈ کو آبادی کے بیسز پر ڈسٹری بیوٹ کرنا شروع کئے تھے اسی سے موجودہ جھگڑا شروع ہوا . . . .

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK: (Anantnag): On a point of order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: What is the Point of Order?

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK: He is talking a about law and order.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Under what rule are you raising the point of order?

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK: 376.

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order.

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK: I have a right to raise my point of order

MR. DEPUTY-SPEAKER: There is no point of order.

SHRI GHULAM RASOOL KOCHAK: I should be given opportunity to answer every issue; I will take one hour.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Order please. There is no Point of Order.

MR. Namgyal to continue his speech.

شری پی - نام گیال : ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ گاڈگل فارمولے میں ۶۰ پرسینٹ پاپولیشن پر ویٹیج دی گئی ہے لیکن وہ جموں و کشمیر میں اپلائی کیا نہیں ہے کیونکہ جب شیخ صاحب پاور میں آئے تو انہوں نے کہا کہ گاڈگل فارمولے کے مطابق ۶۰ پرسینٹ پاپولیشن پر ویٹیج ہے جب کہ جموں و کشمیر میں پاپولیشن کم ہے اور ایریا زیادہ ہے - انہوں نے نیشنل ڈیولپمینٹ کاونسل اور پلاننگ کمیشن کے سامنے اس فارمولا کے خلاف آواز اٹھایا اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے - اب جموں و کشمیر پر گاڈگل فارمولا اپلائی کیا نہیں ہے جو فنڈس ان کو ملتے ہیں وہ زیادہ تر ایریا بیکورڈنیس اور غربت کے لحاظ سے ملتے ہیں لیکن اس چیز کو انہوں نے لداخ اور کارگل کے لئے لاگو نہیں کیا اور کہا کہ وہاں پاپولیشن کے مطابق ملے گا کیونکہ لداخ میں آبادی کم ہے - اسی بات کو لے کر ۱۹۷۹ع میں جھگڑا شروع ہوا -

جب یہ باتیں شروع ہوئیں تو ہم نے کہا کہ آپ سینٹر سے پاپولیشن کے بیسز پر نہیں بلکہ ایریا کے بیسز پر پیسہ لیتے ہیں تو ہمارا ایریا تو پوری اسٹیٹ کا ۲/۳ حصہ ہے ہم کو بھی اسی حساب سے پیسہ ملنا چاہئیے - ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ سٹیٹ کی ۲/۳ ایریا کے حساب سے ہم کو فنڈس ملیں بلکہ ایریا ، پاپولیشن ، ڈسٹینس اور غربت کو خیال میں رکھ کر فنڈس دئے جانا چاہئیں - ہم بہت فار فلنگ ایریا میں بستے ہیں ہمارے ایک طرف چائنہ ہے دوسری طرف پاکستان ہیں- لیکن ہماری باتوں کو نہیں مانا گیا اور ۱۹۸۰ع میں یہیں سے جھگڑے کا آغاز ہوا - لداخ میں اس سوال کو لے کر ایجی ٹیشن ہوا - ہم نے ۲۷ پوائنٹس کو لے کر اپنی مانگیں پیش کیں - جن میں تین چار میجر اشوز تھے اور کچھ چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے - ان میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ سارے لداخ ایریئے کو شیڈولڈ ٹرائبس ڈکلیر کیا جائے - ریجنل اوٹونومی ود ان دی ایسٹیٹ آف جموں و کشمیر کانسٹی ٹیوشن خاص طور سے فائننشل میٹرس میں دی جائے جس میں لا اینڈ آرڈر شامل نہیں تھا - ہم اس میں

ایپلیکیشن آرٹکل چاہئے - اسٹیٹ گورنمنٹ کا کنسینٹ چاہئے - جب اسٹیٹ گورنمنٹ رکمینڈ کریگی کہ سچ ایپلی سچ قانون جموں و کشمیر میں لاگو کرو تب جاکر پریزیڈینشیل آرڈر کے تحت جموں کشمیر میں سیکشن ۳۷۰ کا قانون ایپلی کیبل ہوتا ہے - ابھی تک کوئی سفارش پرائم منسٹر کے سامنے یا ہوم منسٹر کے سامنے نہیں آئی ہے اور ہوم منسٹر صاحب نے اس ہاوس میں دو تین بار ڈیکلائی کیا ہے - کہ کوئی ایسی ریکمینڈیشن ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹمینٹ دیا ہے - وہ سارے فیکٹرس پر بیس نہیں کرتا ہے - اور وہ سارا ڈسٹورٹڈ ہے -

میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیبنیٹ سب کمیٹی اور لداخ ایکشن کمیٹی کے درمیان جو ایگریمینٹ ہوا ہے اس کو امپلی منٹ کرنے کے لئے ہم نے کہا تھا - جب کیبنیٹ سب کمیٹی لداخ آئی تھی تو یہ ایگریمینٹ ہوا تھا جس کے لئے ہم یہاں تک تیار ہیں کہ پرائم منسٹر کی قیادت میں یا ہوم منسٹر کی قیادت میں ایک کمیٹی بنے جس کے لئے میں اپوزیشن لیڈر سے بھی گذارش کروں گا کہ وہ بھی اس میں نومینیٹڈ ہوں اور وہ کمیٹی یہ دیکھے کہ جو ایگریمینٹ ہوا ہے اس میں کیا کیا ایڈمنسٹریشن کی بات کبھی نہیں کہی ہے - ابھی کل ہی جموں کشمیر اسمبلی میں گورنر کے ایڈریس پر جواب دیتے ہوئے وہاں کے فائنینس منسٹر شری تی- تی- ٹھاکر نے ہمارے بارے میں بہت ڈسٹارٹڈ فیکٹس پیش کئے ہیں جو آج کے اخباروں میں شائع ہوئے ہیں - میں سمجھتا ہوں اس طرح کی باتوں سے ساری دنیا اور ملک میں غلط فہمی پیدا کرنے اور گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے - انہوں نے کہا ہے لداخ کے لوگ سپریٹ کیبنیٹ کی مانگ کرتے ہیں - یہ بالکل غلط بات ہے - اور آپ اجازت دیں تو میں ان باتوں کو پڑھ کر سنا سکتا ہوں - انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شیڈیولڈ ٹرائبس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحبہ کے سامنے بات چیت کی تھی اور انہوں نے پی - ایم - بھی یہ کہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہئے انہوں نے (پرائم منسٹر نے) اس کو نہیں مانا ہے - مجھے بڑا افسوس ہے کہ شری ٹھاکر نے اس کو پرائم منسٹر کا نام لے کر ان کو بھی اس میں ڈریگ کرنے کی کوشش کی ہے جبکہ یہ اشو ابھی پرائم منسٹر کے سامنے نہیں ہے کیونکہ کشمیر میں آرٹیکل ۳۷۰ کے تحت اگر سیکشن کوئی قانون جموں کشمیر میں ایپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے

[شری پی نام گیال]

وعدے ہوئے ہیں - وہ بھی اس ایگریمینٹ کو پڑھیں - اور دیکھیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا تیمانڈ کیا ہے - آپ کے سامنے سارے فیکٹرس آ جائیں گے میں اس پر اور زیادہ نہیں کہنا چاہتا بلکہ یہ کہوں گا کہ جو لکھ کر دیا ہے اس کو امپلیمینٹ کرنا چاہئے - فنڈس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے ایگریمینٹ میں میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں -

MR. DEPUTY-SPEAKER: Which Cabinet Sub-Committee are you referring to?

SHRI P. NAMGYAL: This is the agreement reached between the Jammu & Kashmir Cabinet Sub-Committee and the Ladak Action Committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can take something out of it and talk on those lines. But don't read out those agreements.

SHRI P. NAMGYAL: I want to read out only the relevant portion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You need not read it out. You should not mention here the decision of the Jammu & Kashmir Cabinet Sub-Committee.

SHRI P. NAMGYAL: There is no seccrey about this agreement, Sir, and

MR. DEUPTY-SPEAKER: Have you given a copy of it to the Speaker and taken his permission to read it out?

SHRI P. NAMGYAL: No, Sir. But if you permit I will place it on the Table of the House.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can take the idea from it and speak on that basis. You can speak in a general way.

SHRI P. NAMGYAL: I will place it on the Table of the House

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, You can speak something by taking some ideas from them. Now, we are having a general discussion on the President's address.

شری پی - نام گیال : جناب

میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہاوس ایکلائٹنڈ ہو جائے کہ واقعی میں کیا چیز ہے روز روز غلط اسٹیٹمینٹ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے لداخ کے بارے میں نکلتے ہیں - ہم نے جو ریجنل آٹونومی کی جو بات کہی ہے وہ ڈیولپمینٹ امیٹرس تک ہی محدود ہے - لداخ کو الگ کرنے کی بات نہیں کہی ہے - ہم جموں و کشمیر کے کانسٹی ٹیوشن کے تحت ہی بات کر رہے ہیں

We do not want to break away from Jammu and Kashmir.

میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کلیر کہنا چاہتا ہوں - اس لئے یہ ڈسٹارٹیڈ فیکٹس جو جموں اور کشمیر سرکار پریس میں دے رہی ہے اور اسمبلی میں بھی دئیے گئے ہیں - یہ صحیح نہیں ہے اس لئے میں اس ہاوس کے سامنے یہ بات رکھنے جا رہا تھا -

اسی طرح سے شیڈیولڈ ٹرائبس کے بارے میں انہوں نے ہمارے پاس لکھ کر دیا ہوا ہے - کہ وہ

اسٹرونگلی ریکمینڈ کریں گے - سینٹرل گورنمینٹ کو کہ لداخ کے لوگوں کو شیڈیولڈ ٹرائبس ڈکلیر کیا جائے اور لداخ کا جو یہ اشو ہے اس کو سمپیتھیٹکلی لیا جائے گا -

تیسرا یہ اشو تھا کہ جو انہوں نے ڈی لمیٹیشن کمیشن بنایا ہے جموں و کشمیر گورنمینٹ نے جو ڈی لمیٹیشن کمیشن مقرر کیا ہے تو اس میں یہ کہا تھا کہ جب بھی یہ موقع آئے گا تو لداخ کی اسمبلی کانسٹی ٹیونسی بڑھانے کی بات پر غور کیا جائیگا - یہ ساری باتیں ہیں - یہ شیڈیولڈ ٹرائبس کا مین اشو تھا جوکہ وہاں کا بہت امپورٹنٹ اشو ہے - اور جس پر انہوں نے ایگریمینٹ کیا تھا اور جس کے بارے میں انہوں نے ڈسائڈ بھی کیا تھا - ہم لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جو ایگریمینٹ ہوا ہے اس کو پورا کرو - جب یہ وعدے پورے نہیں کئے گئے تو اسی مسئلہ کو لے کر دسمبر ۱۹۸۱ع میں ایجی ٹیشن شروع ہوا اور ۱۵ جنوری ۱۹۸۲ع کو ہمارے تین لیڈر نے ڈیمانڈ کو پریس کرنے کے لئے ان ڈیفینیٹ ہنگر اسٹرائک کی اور آگے چل کر ان کی حالت خراب ہوئی -

اس کے بعد انہیں ڈیمانڈس کو پریس کرنے کے لئے ۲۴ جنوری کو ایک جلوس اس جگہ پر جا رہا تھا جہاں تین لوکل لیڈرز بھوک ہڑتال پر تھے اس پر پولیس نے ان پرووکڈ اور وتھاوٹ وارننگ فائرنگ کی جب بھی فائرنگ کرنا ہوتا ہے تو پہلے وارننگ دی جاتی ہے پھر ہوائی فائرنگ ہوتی ہے اس کے بعد گراونڈ میں رینڈم فائرنگ ٹانگوں کے حصے میں کرنا ہوتا ہے لیکن وہاں پر پولیس نے اس طرح سے فائرنگ کی کہ بندوقوں کو دیوار پر رکھ کر جیسے کہ ٹارگیٹ پر فائرنگ کی جاتی ہے - پولیس کی پہلی گولی سے پہلا آدمی مرا دوسری گولی سے دوسرا آدمی مرا اور تیسری گولی سے تیسرا آدمی زخمی ہوا ان ڈسکریمینیٹ فائرنگ شروع ہو گیا - پچاس ساٹھ گولیاں چلائیں گئی - اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے -

ان سب کے لئے وہاں تو ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے - اسٹیٹ گورنمینٹ سے تو ہم کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں - اگر اسٹیٹ میں جنگل کا قانون چلتا ہے تو یہ سینٹر کی ذمہ داری بنتی ہے - کہ وہ وہاں کے حالات کو دیکھے آج آسام میں کیا ہو رہا ہے ، ناگالینڈ میں کیا ہو رہا ہے ، میزورم میں کیا ہو رہا ہے - جب لوگوں کو

وھاں پر فائرنگ کرنے کے بعد پولیس نے لوٹ مار شروع کر دی یہ لوٹ مار سارے دن رات چلتی رھی کوئی دیکھنے والا نہیں تھا وھاں پر دیپ ھوئے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں توڑ ڈالی گئیں - گھروں میں بچوں اور عورتوں کی پٹائی کی گئی - سامان کو برباد کیا گیا - لوٹ مار کیا گیا -

اس وقت وھاں پر حالت یہ ھے کہ جتنے بھی ھمارے پولیٹیکل پرزنرس ھیں جو لوگ پکڑے گئے ھیں ان کو ضمانت پر نہیں چھوڑا جا رھا ھے - چیف جوڈیشل مجسٹریٹ ایس- پی- اور ڈی- سی- سے پوچھتا ھے کہ ضمانت پر چھوڑوں یا نہ چھوڑوں - اس طرح کی وھاں کے قانون کی حالت ھے - اس وقت بھی وھاں پر دھونا جاری ھے - عورتیں بھی دھرنے پر بیٹھی ھوئی ھیں -

جو لوگ جیل میں ھیں ان کو منی‌مم فیسیلیٹیز نہیں دی جا رھی ھے - پانی تک نہیں دیا جا رھا ھے - حالانکہ یہ لوگ جوڈیشیل لاک‌اپ میں ھیں سرکار کو چاھئے کہ ان کو مینی‌مم فیسیلیٹیز دے -

وھاں پر کبھی کبھی تو مائنس ۲۰ تک ٹیمپریچر ھو جاتا ھے -

[شری پی نام گیال]

تکلیفیں ھوتی ھیں انکی گرایونسز کو کوئی سننے والا نہیں ھوتا تو حالت خراب ھوتی ھے میں کہتا ھوں کہ یہی حالت لداخ میں بھی کبھی نہ کبھی ھو سکتی ھے -

لداخ کے لوگوں نے اس ملک کے لئے بہت خون بہایا ھے ۱۹۴۷ء میں جب اس ملک پر حملہ ھوا کشمیر میں ان ویدرس آئے تھے تو لداخ کے لوگوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا -

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please complete it. You are not coming to national issues. You are still in Jammu and Kashmir only. And you are not speaking about the entire Jammu and Kashmir, but only about Ladhak. Please complete. Your own Party Members will be deprived of their chances.

SHRI P. NAMGYAL: I am going to complete, Sir.

اس کے بعد سنہ ۱۹۶۲ء جب چین نے اس ملک پر حملہ کیا تو اس وقت بھی لداخ کے لوگ آگے بڑھ کر لڑے تھے - پھر پاکستان نے ۱۹۶۵ء میں حملہ کیا اس وقت بھی وھاں کے لوگوں نے اس ملک کے لئے خون بہایا ۱۹۷۱ء کی جنگ میں بھی وہ لڑے - یہ ساری حالت آپ کے سامنے ھے - یہ سب ھوتے ھوئے بھی ھماری وھاں کوئی سنتے والا نہیں ھے -

لیکن ہوٹنگ ایڈجسٹمنٹ تو دور ان کو کمبل تک نہیں دئیے گئے ہیں - کھانے کے لئے ان کو کچھ نہیں دے رہے ہیں - ٹاون سے کافی دور لوگوں کو رکھا ہے اور ان کے رشتہ داروں کو وہاں پہونچنے کے لئے ٹرانسپورٹ نہیں ملتا ہے -

ان سب حالاتوں کو دیکھتے ہوئے میں سرکار سے انورودھ کروں گا کہ کسی نہ کسی منسٹر کو ضرور وہاں پر فوراً جانے کی ضرورت ہے نہیں تو حالات اور ادھک خراب ہو سکتے ہیں - میں ہوم منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ پچھلے دنوں گئے تھے - لیکن موسم خراب ہونے کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے - اب میں ان سے گذارش کروں گا کہ وہ کسی کو وہاں پر اوشیہ بھیجیں - نہیں تو لوگوں کا آپ پر سے وشواس اٹھ جائے گا -

میں کیول سرکار سے ہی نہیں بلکہ پورے سدن سے اپیل کرتا ہوں اور ورودھی دل سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا نمائندہ بھیجیں -

آپ دیکھ لیجئے تو جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اگر آپ کہیں کہ ہم غلطی پر ہیں تو ہم ماننے کے لئے تیار ہیں اگر ہم غلطی پر نہیں ہیں تو جموں کشمیر سرکار سے کہا جائے - کہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کریں اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں -

اس کے ساتھ ہی جو پریزیڈینٹ صاحب کا ایڈریس ہے اس کا میں سمرتھن کرتا ہوں -]

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): Sir, I rise to oppose the Motion of Thanks moved by hon. Ranga Ji, with personal apologies to him.

The principal reason for my opposition is that the overall picture presented in the President's Address does not tally with the experience of the common man. In paragraph 2 of the Address, the year 1981-82 has been called a year of further consolidation. If it is to be admitted that the year 1981-82 was a year of consolidation, then from the common man's experience, it is a year of consolidation of a different type, very different from that envisaged in the Address.

Sir, to the common man, the year 1981-82 is a year of consolidation of monopoly profits, a year of consolidation of the so-called free market operation, i.e., operation by black money, a year of consolidation of the multi-national tentacles on our national economy, a year of consolidation of debt trap laid down by the huge IMF loan, a year of consolidation of subversion of selfreliance, a year of consolidation of the draconian powers in the hands of the ruling party to suppress the toiling people, a year of consolidation of the anti-people internal policies of the Government, and a year of consolidation of the drive towards dynastic rule and subversion of the Constitution

For the toileting people, what has consolidated in the year 1981-82? Grave anxiety and anguish have consolidated in the minds of the millions; anxiety

(Shrimati Geeta Mukherjee)

of the house-wife for the frightful prospect of reeling price rise, despite Government's claims of containing inflation, anguish of the agricultural labourers for less food and less working days in the year, and the anguish of the peasantry for unremunetative price for their produce and anguish of the poorer peasantry for having been consolidated below the poverty line!

But, Sir, apart from the anxiety and anguish, another thing is also being consolidated; and it would be better for the ruling party to come out of the ostrich-like complacency to recognize that simmering and smouldering anger which is being consolidated in the hearts of India's teeming. toiling millions.

But the President's Address fails to take cognizance of all these, and most of the hon. Members speaking from the other side are either totally oblivious to these developments or feign to do so. Otherwise, Sir, how can it be explained that in paragraph 21 of the Address, a disdainful reference. is made of frittering away of national energies "on agitation engineered by sectional interests"? Otherwise, how can speaker after Speaker from the Treasury benches refer to the heroic action of the Indian working class in the nation-wide general strike for their own urgent demands, as well as those of the peasantry and agricultural labourers and other consumers, either as a failure or as a subversion of production? How is it possible? If 19th January was a failure, why did the cities of Bambay and Calcutta, the industrial nerve centres of the country come to a standstill. and appear as a holiday cricket ground according to some of the leading national dailies. Why did Patna Town and inumerable other big or small towns or townlets observe *bundh* in sympathy with the industrial general strike? And as has already been asked in the House, why were 50,000 to 60,000 arrested in connection with the January 19 action? And if the action failed totally, as claimed in the official media and from the Treasury benches here, then why are the spate of victimizations coming in, as the after-math? You cannot say at the same breath that the strike failed and the production was subverted. The reality is that the 19th January strike was a powerful demonstration of the smuldering anger which the ruling party does not want to recognize.

And why should there not be anger?

Look at the complacent claim in paragraph 2 of the Address—rate of inflation was substantially curtailed

What is its impact on an ordinary house-wife's life? Even according to Government's own Economic Survey Review dated December 2—these are mostly under-statement—on Novem ber 14, 1981 she had to buy onion 95.9 per cent dearer compared to Novemaber 15, 1980, chillies 97.9 per cent dearer, fish 46.9 per cent dearer, maize 16.9 per cent dearer, bajra 146 per cent dearer, jawar 12.5 per cent dearer, tea 10.8 per cent dearer, and tea 10.4 per cent dearer

Claims have been made of improved performance of infrastructure. Power generation is state to have increased by 11.3 per cent between April 1981 and January, 1982. What is the guarantee of its steady growth in the background of the admission by the Power Ministry itself recently that there would be a 60 to 70 per cent shortfall in the targeted 3,120 megawatt new generation capacity installation this year, widely reported in all the papers?

15 hrs.

Moreover, what is the overall situation of industrial growth? The National Council of Applied Economic Research in the guarterly review (Jaly to October, 1981) stated that in July the industrial production had increased by 10.2 per cent over the previous month, but in August the increase was only 9 per cent in September, 8.6 per cent and in October 7.5 per cent. In plain-words, it is going down And the NCEAR is not a leftist organisation!

Thanks to better monsoon and of course the tenacity of the farmers the foodgrain production is expected to increase. It is claimed to be 132.9 million tonnes in 1981-82. But why does not the Address refer to the fact that the target was 138 million tonnes? It has been claimed that fertilizer production will increase this year. But why does the Address not state that the annual growth rate of the use of chemical fertilizers has comparatively declined? Does it not reveal anything that while the annual growth rate of the same in 1978-79 increased by 19.3 per cent over the previous year, in 1979-80 it increased only by 2.7 per cent, and if that is considered to be due to draught, in the year 1980-81 when there was no draught the increase was only 6.1 per cent, i.e; nowhere near the 1978-79 rate? It does reveal the growing impoverishment of the peasantry due to unfavourable terms of trade, due to unremunerative price of their produce And is it not a fact that by the end of 1980 the dowest rung of the peasantry along with agricultural labourers and the urban poor has been pushed below the poverty line swelling the ranks of those below the poerty line to 50.82 per cent of the population? 1981-82 will make it even worse.

Para 13 of the Address claims that "the Government is vitally concerned with the welfare of the workers". The Address has reminded us that the year 1982 will be observed as Productivity Year by the Government. In this so-called Productivity Year what are the 'welfare' measures adopted and proposed for the workers? Apart from what has been already observed by some of my colleagues in the Opposition extension of N.S.A: to 16 sectors —in fact to all sectors virtually—there is a reported directive of the Finance Minister that the managements of the public sector enterprises in coal, steel and of BHEL are not to start any fresh wage revision negotiations. The net upshot is that when some of the wage agreements expire in 1982 there would be a wage-freeze. Private sector would naturally go half a league onwards. It is being said that the wages will be linked with productivity. But does productivity depend only on workers? Are not there so many factors like power shortage, raw material availability etc., which are beyond their control? Moreover, in the monopoly market condition do not many industrialists prefer shortage when shortage pays better? Is it under the workers control? Without settling these questions, linking productivity with wage will be a welfare measure" for the worker indeed!

The Address claims "greater social justice". What social justice is there in reducing the worker's real wage with a vengeance knowing fully well that between 1970-71 and 1978-79 the share of wage incomes in the total factor of payments in the manufacturing sector declined from 58 to 54 per cent while profits and dividends increased between 1972-73 and 1978-79 to 28.8 per cent from 25.5 per cent. And by 1981-82 the wage percentage has further deteriorated while the profit percentage has substantially increased. It is evident from the latest *Economic Times* Survey dated 25th May, 1981 which stated that the gross profit of the 101 largest private sector companies increased by 15.3 p.c: in 1978-79 and 19.4 p.c. in 1979-80: That this trend is further consolidated can be seen in some of the company profits in 1981 over 1980, in this period Premier Auto Profits increased by 129.7 p.c: TISCO's profit by 108.8 p.c.: and Mukand Iron's profit by 67.6 p.c.: Wages freeze for workers and all-out encourgement for profit for the big capitalists—social justice ideed!

According to the President's Address, the revised 20 point programme is supposed to provide the basis for further growth along with stability and greater social justice—para 2— and is supposed to impart greater dynamism to some key social and economic programmes included in the sixth plan—para 145. For lack of time, I give only one illustration which will debunk the proposition. While the sixth plan fixed

(Shrimati Geeta Mukherjee)

1981-82 as the target year for completing taking possession of the surplus land, and completing the distribution of the same, the revised 20 point programme has pushed back the target year to 1985. And, I believe, land reform was considered a key socio-economic programme. The revised 20 point programme is dynamic indeed, but in reverse gear!

If dynamism was lacking in laid reform, it was offset by dynamism in making the door wide open for foreign private capitalist collaboration for luring IMF. The number of foreign collaborations rose from 262 in 1979 to 576 in 1980. And surely in 1981 it has flowered even more profusely.This is the situation with the slogan of self-reliance, which has again been repeated in the Address

And, political stability? The President in his Republic Day message said,

> " In the faithful working by all of us of the constitution.... lies the guarantee of the nation's political stability"

For obvious reasons, he cannot repeat all this in this Address. But sometimes unsaid words are more potent than the words said. According to the yardstick of his Republic Day message, can the claim of political stability made in this Address be sustained after what is happing in Kerala where the Speaker is propping up the minority Government or after what is happending in West Bengal where by hook or by crook the elections are sought to the postponed? Are these acts consistent with the spirit of our Constitution? Does not the brazenfaced defence of the idea of Presidential form of Government by a stalwart of the ruling party in this very debate—Shri Janaganath Rao is not here—go contrary to the guarantee to the nations political stability"? Mr. Rao has come. I think he has followed the Republic Day message of the President!

A few words about law and order. I want to bring one case to your notice very seriously. In U.P: in the constituency of Shri Jharkhande Rai our member who is today ill, there was a comrade of ours? I am sorry to say "was". He was a very good comrade—Shri Ram Senahi Roy. He belonged to village Khaira Mohammadpur in Ghosi constituency, District Azamgarh. I am sorry to tell you that in the name of encounters with dacoits, he was dragged from his house at night and was shot dead point blank.**

It is a serious affair.

If the murder of 960 Harijans be in 1980-81 is a national shame, surely the bigger share of the shame has to be borne by the ruling party. Sir, they have asked for cooperation. If the ruling party cooperate with the teeming millions, with the toiling millions of the country, they will automatically get our cooperation. Some friends said that we are not saying what the Government should do for getting our cooperation. Here are some of our proposal for that: Strengthen the anti-imperialist content of India's non-aligned policy. Withdraw NSA and ESMA. Give up the drive towards Presidential form of Government Cancel IMF deal. Stop penetration of multi-national corporations. Restructure Centre-State relations to expand the powers and resources of the states. Take stringent action against black money. Nationalise monopoly houses, foreign companies and foreign trade.

Take over wholesale trade in foodgrains and essential commodities and distribute the same at fair price. Give a fair deal to workers by dropping the idea of wage freeze, guaranteeing need-based minimum wage and stopping layoff, lock-out and closures. Implement land reform on war-footing, guarantee employment and minimum wage

**Expunged as ordered by the Chair.

to agricultural labourers and remunerative price to peasants. Include the right to work in the Constitution as a fundamental right. Stop atrocities on Harijans, scheduled tribes and weaker sections. Take effective steps to root out corruption.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Another 20 point programme!

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: This is the platform for cooperation. This is the platform given by the teeming millions. Since it does not agree with the President's Address, I am sorry to oppose the Motion of Thanks.

SHRI RAJESH PILOT (Bharatpur): Sir, I rise to support the motion moved by our very senior colleague, Prof. Ranga. I have been listening to the speeches from both sides. Honestly speaking, the idea which arose in my mind was, anywhere if different teams are there, they do appreciate each other's point. After a goal is scored in football or hockey or after a sixer is scored by a cricketer, they go to the opposite side and express their appreciation. But in this profession of politics, I have seen in these last two years, none of the points has been appreciated by this opposition. I fail to understand this. In two years, have we not done even a single thing which is good? Have we not taken any action which is in the interests of the nation? I fail to understand how nobody from that side has said that even 0.1 per cent of what has been done by this Government is good. This is my own assessment and that is what I have been thinking about. This profession seems to be very different from the common thinking of the citizens here. Yesterday, I was listening to Mr. George Fernandes. He spoke about Bombay. He said that 2.5 lakh people were ready to be arrested but there was no place in jails. I failed to understand as to what was the necessity of mentioning that point. Jails are meant for anti-social elements. If required, the house of every anti-social element will become jail. But I am very sorry to say that if such type of feeling prevails in the country and if this is the attitude of the opposition, I do not know how far we can take our nation on the road of development.

It is very difficult for any noble person to praise himself or his institution or his party. Our Government have produced documents giving their achievements with fact and figures. Those documents are available with the opposition also. Instead of criticising the Government and saying that this Government has not achieved anything on any front, they must go on record and tell the Government that such and such figures are wrong. This type of negative attitude by the opposition should be avoided and they should think for the betterment of the nation.

The other day, I read an appeal by a very senior politician of this country. He writes in his appeal that my heart is for the Harijans'. I have read in the newspapers that people in his constituency could not vote for 30 years. It was only in 1980 elections that they saw a ballot paper for the first time. How can such people who cannot look after the Harijans in their own constituencies, boast for the Harijans and give apeal to the nation that 'my heart is for the Harijans if I am not mistaken, one Harijan was to be elected as the Prime Minister of this country. I am very sorry to say that— I read in the newspapers—he was the only politician who said that a Harijan could never become the Prime Minister of this country. This is the attitude we politicians have get.

A senior Member, Shrimati Geeta Mukherjee has said that prices of chillies, rise and wheat have gone up. On the one hand, you say, give better price to the farmers and on the other hand, you say, give cheaper price to the consumers. How can it be possible? Look at our Government. They have given better prices to our farmers in respect of wheat, rice, sugarcane, etc. If you give better price to the farmer, can you give cheaper price to the consumer? It has to be in equal proportion. If you raise the price for the farmer, the consumer has to suffer

[Shri Rajesh Pilot]

to that extent. This doubletalk is damaging the nation. This double talk in the opposition should be stopped for the future of the nation.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Why do you not permit double talk at least by the politicians?

SHRI RAJESH PILOT: Now, I would like the Government to take note of a few suggestions which I have in mind.

My first sugegstion about communal riots is that by this time, the Government has been able to identify certain sectors or spots where communal riots are taking place. Although you have given instructions to the State Governments to form regional working groups to find out the causes, scientific and historical background of these riots, I request the Government to take strict action in this direction.

Our public sector undertakings have to play a very crucial role in the economy of the nation. We must pay a very high attention to these undertakings.

Every Government which comes into power, must talk about the farmer and the labour but does nothing about them. I would like to request our Government that whatever steps you take for their welfare in your own circumstances, please see that they must reach them. Whatever decision we have taken must reach those people for whom it is meant. They must get the benefit which the Government intend to give them. Let us not stop half way. They must be implemented very strictly so that the farmers get the help.

Coming to irrigation facilities and drinking water facilitie , I am sorry to say that even now, 34 years after independence, there are places where a person has to walk 8 km to fetch drinking water in States like Rajasthan and Madhya Pradesh. It is a very sorry state of affairs. Water is one of the prime necesities of human beings. So, Government must give top priority to drinking water facility and also irrigation facilities in those few States, which are lacking them. For instance, the construction of the Rajasthan canal was being given top priority. But now it is lagging behind for want of finance. We have to give priority to these projects so that the irrigation facilities can be improved.

We have a lot of schemes to help the poor people, those whose income is below a particular level, like interest free doans and subsidies of different types. But I am sorry to point out that even though Government have so many schemes, they do not reach the common man in a proper shape. There is some flaw somewhere between the decision making and benefit receiving end. So, it should be ensured that whatever is given to the poor people reach them in a proper form.

I am happy to note that the Government have established the National Bank for Agriculture and Rural Development. This is a very good idea. It is a very good thing that they have decided to set apart a big amount for the betterment of the rural people. I would request the Government to take it up on a war footing so that development takes place at a faster pace.

The NREP and IRDP are very good schemes. We have to make them a success so that the nation can march on the road to development. But there are many obstacles in the way. For example, Government approve many schemes. Before the implementation has just started, there comes a stay order from the court and the entire work come to a halt. Government have to give serious thought to this aspect and find out a way by which this business of stay order can be tackled. Take the question of road building. Government approve the construction of a particular road; the very next day the matter is taken to court by some private party and a stay order is issued. There are cases where roads, the construction of which has been approved 15 years ago, could not be executed

because of such stay orders by the court.

After all, we have been elected by the people. The people have put the Government, rather the party in power, to rule the country. So, we must produce results removing all obstacles in the way. Because, we cannot tell the electorate after five years that we could not construct roads, or take up other development work, because of stay orders from the court. So, we have to find a solution where the stay orders will not be a hurdle to the execution of development schemes.

In the field of social justice, Government have to take measures to remove social evils like dowry. The removal of economic disparity should also be given top priority. Otherwise, these differences will not only continue but will get aggravated.

It is not easy to make progress in the field of development in a big country like ours. It takes a litle longer to correct the imbalances deliberately created and to march forward meaningfully. In spite of all the difficulties, the progress which has been achieved in the last two years is commendable, especially after the severe set back of the earlier three years.

As an obedient member, I want to conclude my speech within the time allotted to me. I conclude by supporting the Motion of Thanks to the President's Addres so ably moved by Prof. Ranga.

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : डिप्टी स्पीकर साहब —

अमल से दुनिया बनती है,
जन्नत भी जहन्नुम भी,
यह ख़ाकी अपनी फितरत से,
न नूरी है न नारी है ।

मैं सब से पहले हरिजनों के मसले को ही लेता हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम है । हमारे जो सदस्य अभी बोले हैं, बहुत शान्दार बोले हैं, "ठाकुर हैं न ।" उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है । मुझे पता है कि कौन-कौन हमारे हितैषी हैं, लेकिन हरिजनों के साथ जो सुलूक हुआ है, क्या हम उस को भूल सकते हैं । इस में ठाकुर का कुसूर नहीं है, मैं जमीदारों को बात कर रहा हूं ....

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : ये अपनी ही पार्टी के हैं ।

श्री सुन्दर सिंह : जो आज सब से बड़ा जमीदार है वह ठाकुर है, राजपूत है और इन्होंने ही हमारा सत्यानाश कर रखा है । लैंड रिफार्म आया लेकिन इन्होंने नहीं होने दिया, जमीनें अपने पास रखीं, न हरिजनों को दीं और न छोटे जमीदारों को दीं । लेकिन नाम इन का लेते हैं, क्योंकि उनसे वोट लेने हैं । स्टेटों में भी यही हालत है, सब जमीदार छाये हुए हैं । हर एक आदमी कहता है कि किसानों को देना चाहिए, मैं पूछता हूं किसानों के सिवा किस को मिल रहा है, क्या हरिजनों को मिल रहा है ? एक मज़े की बात यह है कि ये न कांग्रेस को कुछ देते हैं और न कम्यूनिस्टों को देते हैं, लेकिन कम्यनिस्ट वाले भी उन्हीं का नाम लेते हैं । शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को आप ने अलग-अलग कर दिया है, जिस की वजह से आज हमारे पास कोई लीडरशिप बाकी नहीं बची है । हम को इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन अलग-अलग होने से हमारी लीडरशिप खत्म हो चुकी है जिस की वजह से लड़ाई होती है ।

हमारे बाबू जगजीवन राम कहां जा बैठे हैं ? लोक दल में मिल गये हैं, उस लोक दल में जिस ने पिछले चुनावों में हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया । चौधरी चरण सिंह और देवी लाल ने हम को

(श्री सुन्दर सिंह ज०)

वोट नहीं डालने दिया। भाई, तुझे अगर आना ही था, तो हमारी तरफ़ आ जाता। भाई चह्वाण जी आ गये, तुझे भी आ जाना चाहिए था। उधर तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है।

हरिजनों में तभी जान आ सकती है जब इन के अन्दर लीडरशिप मौजूद हो। ज्ञानी जो, हमारे ऊपर रहम करो, आप तो हमारे हितैषी हैं, आप का ख्याल हमारी तरफ़ है। मैं जाटों की बात करता हूं—हमारे यहां पंजाब में यह कहानी है कि *ये तो भट्टम ही भट्टा बैठा रहे हैं। आज हमें जमीदारों से जो तकलीफ है वह किस वजह से है? कांग्रेस शुरू से यह नारा लगाती रही—"लैण्ड-रिफार्म, लैंड-रिफार्म।" लेकिन हुआ कुछ नहीं, न उन्होंने कुछ किया और न इन्होंने कुछ किया, सिर्फ हमारे साथ हमदर्दी दिखालाते रहे। ये जो 980 आदमी मर गये, हरिजन बेचारे मारे गये, इस के लिए कौन ज़िम्मेदार है? इस में ज्ञानी जी का कुसूर नहीं है, कुसूर इन का है। अगर आप सिन्सीयर हों तो कोई कैसे हरिजनों को मार सकता है। आप के अन्दर सिन्सीयेरिटो नहीं है, इसी लिए हरिजन आप को वोट नहीं डालते। श्री राम जेठमलानी को रंगा साहब कहते हैं कि हमें काआपरेशन दो। आप को काआपरेशन दे कर क्या उन को मरना है? यह सीधो सी बात है। वह आप को काआपरेशन क्यों देगा। हां, श्री मधुदंडवते जी से काआपरेशन लो, तो वह दे देंगे, लेकिन वह बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि उस को स्मगलर्स के केस लड़ने हैं।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You can continue tomorrow. We have to take up Private Members Resolutions.

SHRI RAJESH PILOT: Some of the words in his speach should not go on record.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I will go through the speech.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up Private Members' business.

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

THIRTY-FIFTH REPORT

SHRI T. R. SHAMANNA (Bangalore South): I beg to move:

> "That this House do agree with the Thirty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 24th February, 1982",

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House do agree with the Thirty-fifth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 24th February, 1982."

The motiin was adopted.

15.31 hrs.

RESOLUTION *RE.* WELFARE OF CONSRUCTION WORKS— Conted.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We shall no take up further consideration of the resolution re; welfare of construction workers moved by Shri M. M. Lawrence on 18th December, 1981.

SHRI M. M. LAWRENCE (Idukki): The construction workers in India are the most exploited lot of our working people. Though about 4 million workers are engaged in various activities of construction in several projects the rondition of these workers is miserable and shocking. There is no security of employment. As soon as the contract ends or the work is comple-